September 2021

Media Coverage Report

Wahoo Communication

Prepared by: Team Health & Food

Approved by: Nitish Kumar,
Director

Strong Warning Labels on Unhealthy Food Products

Webinar held by
Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) and Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi)

Press Release

In collaboration:

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) in partnership with Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) -IAP Nutrition Chapter, Epidemiology Foundation of India (EFI), Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and Indian Public Health Association (IPHA).

Press Release

Strong Warning Labels on Unhealthy Food Products is a Human Right: Public Health Experts Call for Urgent Action

New Delhi: 27 August 2021. Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) http://www.napiindia.in/ and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Dr.Suneela Garg, President , Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and she said *"Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth .Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs."*

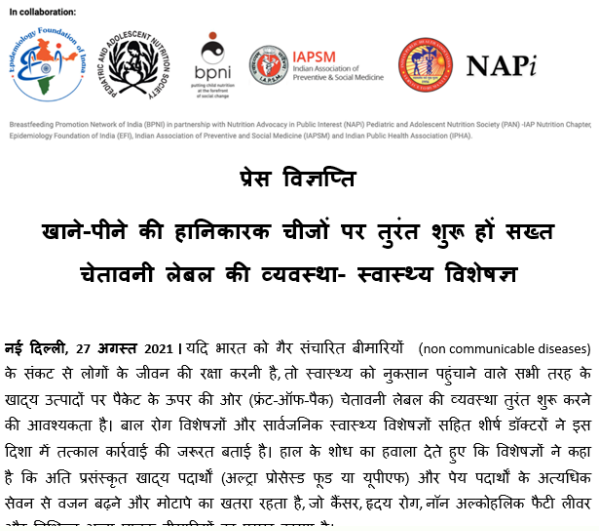
In collaboration:

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) in partnership with Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) -IAP Nutrition Chapter, Epidemiology Foundation of India (EFI), Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and Indian Public Health Association (IPHA).

प्रेस विज्ञप्ति

खाने-पीने की हानिकारक चीजों पर तुरंत शुरू हों सख्त चेतावनी लेबल की व्यवस्था- स्वास्थ्य विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 27 अगस्त 2021 | यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों (non communicable diseases) के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर (फ्रंट-ऑफ-पैक) चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित शीर्ष डॉक्टरों ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है। हाल के शोध का हवाला देते हुए कि विशेषज्ञों ने कहा है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या यूपीएफ) और पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा रहता है, जो कैंसर, हृदय रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर

COVERAGE REPORT

Media Kit

മലയാള മനോരമ

Malayala Manorama

അൾട്രയെങ്കിലും അപകടം അരികെ

• അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ

ന്യൂഡൽഹി • പാക്ക് ചെയ്തെത്തുന്ന 'അൾട്ര പ്രൊസെസ്സ്ഡ് ഭക്ഷ്യ പദാർഥങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ. അനാരോഗ്യത്തിലേക്കു നയിക്കാനിടയുള്ള ഇത്തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പാക്കറ്റിൽ മുന്നറിയിപ്പു (വാണിങ് ലേബൽ) ഉറപ്പാക്കുന്നത് അവകാശമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അൾട്ര പ്രൊസെസ്സ്ഡ് ഭക്ഷ്യ പദാർഥങ്ങളും പാനീയങ്ങളും കാൻസർ ഉൾപ്പെടെ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്നുവെന്ന പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്.

വിവിധ ബ്രാൻഡുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്തെത്തുന്ന സംസ്കരിച്ച മാംസം, പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ്, മിഠായി, സോഡ, ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് സൂപ്പ്, ചൂടാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഫ്രോസൺ വിഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അൾട്ര പ്രൊസെസ്സ്ഡ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽപെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പൊണ്ണത്തടി, അമിത ഭാരം എന്നിവയിലേക്കു നയിക്കുകയും കാൻസർ, ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കരൾരോഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യാം.

ബ്രസ്റ്റ്ഫീഡിങ് പ്രമോഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ന്യൂട്രിഷ്യൻ അഡ്വക്കസി ഇൻ പബ്ലിക് ഇന്ററസ്റ്റ്, അഡോളസെന്റ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ സൊസൈറ്റി, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രിവന്റീവ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ, എപ്പിഡെമിയോളജി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ എന്നിവർ ചേർന്നു സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറിലാണ് വാണിങ് ലേബലുകൾ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിദഗ്ധർ ഉന്നയിച്ചത്. നേരത്തെ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനു നേരിയ തുടക്കമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇതു വ്യാപകമായിട്ടില്ല.

പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണം കേടാവാതിരിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസപദാർഥങ്ങളും സ്വാദിഷ്ഠമാവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകളും അംഗീകൃതമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഈ രാസപദാർഥങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും പാക്കറ്റിലാക്കുമ്പോഴും പുതിയ രാസമിശ്രിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാസമിശ്രിതങ്ങളാണ് രോഗകാരണമാകുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ഇതുകൊണ്ടാണ് വാണിങ് ലേബൽ എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിൽ കാൻസർ സാധ്യത വളരെക്കൂടുതലാണെന്നു പഠനങ്ങളുണ്ട്.

എത്ര കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം രോഗ സാധ്യതയും കൂടുമെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Media Kit

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
www.livehindustan.com

X

खाद्य पैकेटों पर चेतावनी अनिवार्य करने की मांग

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

देश के शीर्ष डॉक्टरों और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खाद्य सामग्री के पैकेटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी को अनिवार्य बनाने की मांग की है।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) की अध्यक्ष डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकारें ज्यादा चीनी, नमक या वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के पैकेट पर चेतावनी वाले लेबल लगाएं। यह बात उन्होंने बीपीएनआई की ओर से इस विषय पर आयोजित वेबिनार में शुक्रवार को कही।

ब्राजील के साओ पाउलो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर न्यूट्रिशन में पब्लिक हेल्थ की अध्यापक और विशेषज्ञ नेहा खंडपुर ने साक्ष्यों को पेश करते हुए कहा कि उपभोक्ता को जागरुक करने और उनके निर्णय को प्रभावित करने में ऐसी चेतावनी सबसे प्रभावी पाई गई है। न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता ने कहा कि बीमार करने वाले खाद्य उत्पादों के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा ऐसे नियम अनिवार्य होने चाहिए।

NBT
नवभारत टाइम्स

'खाद्य उत्पादों के ऊपर लगें वॉर्निंग वाले लेबल'

एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली : एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देश में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर चेतावनी लेवल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की जरूरत है। एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर जोर दिया। वेबिनार की अध्यक्षता आईएपीएसएम अध्यक्ष डॉ. सुनीला गर्ग ने की। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि सरकारें मोटापे और नॉन-कम्युनिकेवल बीमारियों से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या सेचुरेटेड फैट वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे उपाय करे।

Media Kit

राजस्थान पत्रिका

पत्रिका UTTAR PRADESH

पत्रिका
मध्यप्रदेश की सबसे बुलंद आवाज़

खाने में बीमारी को दावत | पत्रिका की मुहिम में जुड़े विशेषज्ञ

'अगली पीढ़ी को बचाने फूड पैकेट चेतावनी तुरंत शुरू करें'

वैज्ञानिक शोधों का हवाला, ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से खतरा अधिक

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. पैकेटबंद खाने-पीने की चीजों से आगाह करने के लिए अब देश भर के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और संगठन आगे आ गए हैं।

इन्होंने कहा है कि अगर देश को बीमारियों के बड़े खतरे से बचाना है तो ऐसे उत्पादों पर सेहत संबंधी चेतावनी तुरंत शुरू करना बहुत जरूरी है।

इन्होंने वैज्ञानिक शोधों का हवाला दिया है जिनमें साबित हुआ है कि ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से कैंसर, हृदय रोगों और लिवर रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है।

13 जून, 2021 और 14 जून, 2021 को प्रकाशित खबर

शोधों में चेतावनी कारगर...

ब्राजील के साओ पाउलो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर न्यूट्रिशन में पब्लिक हेल्थ की अध्यापक नेहा खंडपुर ने विभिन्न देशों में हुए शोध के आधार पर कहा है कि नगक, चीनी और वसा के संबंध में लोगों को स्पष्ट जानकारी देने वाली चेतावनी बहुत प्रभावी पाई गई है। इसकी मदद से लोग बेहतर उत्पाद चुन पाते हैं।

टालने में जुटी है इंडस्ट्री

एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने कहा है कि फूड इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए ऐसी चेतावनी की व्यवस्था में देरी करवाना चाहती है। साथ ही यह पुरजोर कोशिश कर रही है कि सरकार इस संबंध में अगर नियम बनाए भी तो वे बहुत सख्त नहीं हों।

पैकेटबंद चीजों पर चेतावनी जरूरी

ये संगठन पैकेटबंद चीजों पर सामने की ओर चेतावनी के नियम को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आए हैं- न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई), इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आइएपीएसएम), पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी, एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई)।

सेहत सबका हक

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आइएपीएसएम) की अध्यक्ष डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा "स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सरकारें ज्यादा चीनी, नमक या वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के पैकेट पर ऊपर की ओर ही चेतावनी वाले लेबल के नियम अपनाएं।"

भारत में बढ़ा मोटापे का खतरा

न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता ने कहा कि बीमार करनेवाले खाद्य उत्पादों के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसे तुरंत नहीं रोका गया तो आने वाले दशक में भारत भी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मोटापे से ग्रसित देशों में शामिल हो जाएगा। जब तक ऐसे नियम अनिवार्य नहीं बनाए जाएंगे, इंडस्ट्री इसका पालन नहीं करेगी। क्योंकि उनका स्वार्थ सिर्फमुनाफा कमाने को लेकर है।

COVERAGE REPORT

Media Kit

the pioneer

Experts for adopting front-of-pack labels on all processed foods

PNS ■ NEW DELHI

'FOPL can allow for a paradigm shift in the food consumption pattern'

If India is to safeguard its people's lives, particularly children, from the looming crisis of deadly non communicable diseases (NCDs), it needs to urgently and mandatorily adopt front-of-pack warning labels (FOPL) on all ultra processed foods (UPF), health experts said here on Friday.

They have reasons. According to Euromonitor estimates, the sale of UPF has increased from 2 kg per capita in 2005 to 6kg in 2019 and is expected to grow to 8kg in 2024. Similarly, beverages have gone up from less than 2 Litres in 2005 to about 8 Litres in 2019 and are expected to grow to 10 Litres in 2024. Unchecked consumption of these UPF is leading the country's youth to overweight and obesity.

At a webinar held here to discuss the issue threadbare, experts felt that though simple consumer-friendly moves, FOPL can allow for a paradigm shift in the food consumption pattern of the country and as a result, avert an impending NCD crisis, saving many lives.

"Right-to-health is a fundamental right of every person. Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of wasteful nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs," said Dr.Suneela Garg, President , Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM), at the webinar.

Presenting evidence from around the world, Neha Khandpur, faculty of public health from University of Sao Paulo, Brazil's Centre for Nutrition informed, "Warning labels have consistently been shown to be most effective at improving consumer understanding, at influencing their purchase decisions and at supporting healthy food choices. They also are most likely to encourage product reformulation. Warning labels are the strongest nutrient-based label that India should consider implementing".

Dr Arun Gupta , convenor of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), a national think tank working on nutrition policy, said, "This is happening at a time when India is showing a tremendous rise in sales of UPF items both in the category of food and beverages.

Media Kit

millenniumpost
NO HALF TRUTH

PACKAGED FOOD

Experts demand rollout of strict front packaging norms at the earliest

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: In view of the increasing threat of non-communicable diseases among children due to intake on high amount of salt, fat and sugar contents in packaged foods, the doctors as well as experts have asked the Food Safety Standard Authority of India (FSSAI) to implement package levelling norms at earliest.

Citing scientific researches, the experts have stated that excessive intake of salt, fat and sugar contents in packaged food products is becoming a major cause of cancer, heart diseases and liver diseases.

Consumer rights activist and columnist Pushpa Girimaji said, "To protect the interest of citizens, food items with high salt, sugar and fat should be introduced with colour coding or any other easily understandable warning labels."

While addressing a webinar, Dr Sunila Garg, who heads Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM), said, "Everyone has the right to have a better health and health of younger generation is the wealth of the nation. So, it is a must for state and central governments to put warning labels on top of the front of packaging of food products."

Experts from the Pediatric and Adolescent Nutrition Society and Epidemiology Foundation of India have said that the food industry wants to delay the system of such warnings for its own benefit and they the industry is trying to ensure that the rules are not strict.

Citing research findings, Neha Khandpour, professor of public health at the Centre for Nutrition at the University of So Paulo, Brazil, stressed that such warnings have been found to be most effective in informing consumers and influencing their decisions as people are able to select better products on the basis of such warnings.

"There has been a rapid increase in the use of food products that cause sickness. In the coming decades, India will also join the obesity-prone countries like Britain and America. The rules are to be made mandatory, else industry wouldn't follow it," said Arun Gupta, who is convener of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPI), at a webinar organised by BPNI.

CELEBRATING 75 YEARS OF INDEPENDENCE

Media Kit

मेत पारी की शुरूआत करेगी। को ही जारी कर दी गई थी।

हानिकारक खाने की चीजों पर सख्त चेतावनी लेबल की मांग

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर (फ्रंट-ऑफ-पैक) चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित शीर्ष डॉक्टरों ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है। हाल के शोध का हवाला देते हुए कि विशेषज्ञों ने कहा है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या यूपीएफ) और पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा रहता है, जो कैंसर, हृदय रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और विभिन्न अन्य घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है। शुक्रवार को आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर बल दिया। वेबिनार की अध्यक्षता डॉ. सुनीला गर्ग, अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) ने की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और गैर संचारित बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे नियामकीय उपायों को अपनाएं।

साओ पाउलो विश्वविद्यालय, ब्राजील के सेंटर फॉर न्यूट्रिशन की पब्लिक हेल्थ फैकल्टी और विशेषज्ञ नेहा खंडपुर ने दुनिया भर में जुटाए जा रहे साक्ष्यों को पेश करते हुए कहा, ष्उपभोक्ता की समझ में सुधार करने, उनके खरीदने के निर्णयों को प्रभावित करने में ऐसे खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल का होना सबसे प्रभावी पाया गया है।

Media Kit

हानिकारण चीजों पर चेतावनी लेबल लगाने की अपील

नई दिल्ली। यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है।

डॉ. सुनीला गर्ग, अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आईएपीएसएम ने कहा स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है।

इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और एनसीडी के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे नियामकीय उपायों को अपनाएं।

Media Kit

रक्षा बलों के ओलंपियनों को किया सम्मानित
पेज-14

आलाकमान ने भूपेश बघेल को दिया अभयदान
पेज-11

हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जनता की भूमिका सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए
-ओम बिरला@ombirlakota

केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से ई-वाहन अपनाने का आग्रह
पेज-15

www.facebook.com\rashtriyasahara https://twitter.com/SaharaRashtriya www..rashtriyasahara.com

शिल्पा ने 'गलतियां' करने पर गुप्त पोस्ट साझा किए
पेज-16

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता ■ कर्त्तव्य ■ समर्पण

■ नई दिल्ली ■ लखनऊ ■ गोरखपुर ■ पटना ■ कानपुर ■ देहरादून ■ वाराणसी से प्रकाशित
नई दिल्ली
शनिवार ● 28 अगस्त ● 2021
16+4 (हस्तलेख) पृष्ठ, मूल्य ₹ 4.00

सर्राफा दिल्ली सोना (प्रति 10 ग्राम) ₹ 46,312 | चांदी (प्रति किलो) ₹ 61,667 | शेयर संसेक्स 56,124.72 + 175.62 | निफ्टी 16,705.20 + 68.30 | विनिमय दर ₹/$ 73.69 + 0.53 | मौसम (दिल्ली) तापमान अधिकतम 37° न्यूनतम 27°

खाने-पीने की वस्तुओं पर सख्त चेतावनी के लेबल की व्यवस्था शुरू हो : स्वास्थ्य विशेषज्ञ

नई दिल्ली (एसएनबी)। यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर (फ्रंट-ऑफ-पैक) चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित शीर्ष डॉक्टरों ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है। हाल के शोध का हवाला देते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या यूपीएफ) और पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा रहता है, जो कैंसर, हृदय रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और विभिन्न अन्य घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है।

खाने-पीने की चीजों में हानिकारक कारकों की मौजूदगी की चेतावनी दी जाए

बीपीएनआई,एनएपीआई सहित कई स्वास्थ्य संगठनों ने भारत सरकार से इसकी अनिवार्यता पर तत्काल विचार करने की अपील की

ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई), न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) सहित कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने भारत सरकार से ज्यादा चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल की अनिवार्यता पर तत्काल विचार करने की अपील की है। शुक्रवार को आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर बल दिया। वेबिनार की अध्यक्षता इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की अध्यक्ष डा. सुनीला गर्ग ने की।

उन्होंने कहा स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और गैर संचारित बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे नियामकीय उपायों को अपनाएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि फूड इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए चेतावनी लेबल संबंधी दिशा-निर्देशों में देरी करवाना चाहती है। साथ ही इसकी कोशिश है कि नियम सख्त नहीं हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिब्बा-बंद खाद्य पदार्थ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं।

COVERAGE REPORT

Media Kit

अमृत इंडिया नई दिल्ली, शनिवार, 28 अगस्त, 2021

खाने-पीने की हानिकारक चीजों पर तुरंत शुरू हो सख्त चेतावनी लेबल की व्यवस्था

नई दिल्ली । यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। शुक्रवार को आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर बल दिया। वेबिनार की अध्यक्षता डॉ. सुनीला गर्ग, अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आईएपीएसएम ने की। उन्होंने कहा स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और गैर संचारित बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे नियामकीय उपायों को अपनाएं। पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी और एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने कहा कि फूड इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए चेतावनी लेबल संबंधी दिशा-निर्देशों में देरी करवाना चाहती है। साथ ही इसकी कोशिश है कि नियम सख्त नहीं हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिब्बा-बंद खाद्य पदार्थ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। नेहा खंडपुर ने दुनिया भर में जुटाए जा रहे साक्ष्यों को पेश करते हुए कहा उपभोक्ता की समझ में सुधार करने उनके खरीदने के निर्णयों को प्रभावित करने में ऐसे खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल का होना सबसे प्रभावी पाया गया है। इनकी वजह से उपभोक्ताओं को स्वस्थकर खाद्य उत्पाद चुनने में आसानी होती है। साथ हीए इनसे उत्पादों में सुधार की संभावना भी ज्यादा रहती है। डॉ अरुण गुप्ता ने कहा ठखाद्य और पेय दोनों श्रेणी में भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यूपीएफ प्रॉडक्ट्स की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अगर हम अभी इस पर रोक नहीं लगाते हैं, तो आने वाले दशक में भारत भी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मोटापे से ग्रसित देशों में शामिल हो जाएगा।

COVERAGE REPORT

Media Kit

PRAGATHI EXPRESS

RNI Regd. No. TELENG/2013/50818

ENGLISH DAILY HYDERABAD TELANGANA

Vol No: 9 | Issue No : 41 | Saturday, August 28, 2021 | Pages-8 | Rs. 1/

PRAGATHI EXPRESS
HYDERABAD-TELANGANA
SATURDAY, AUGUST 28, 2021

US EXIT SPELLS FEAR, UNCERTAINTY FOR AFGHANS

US President Joe Biden has asserted that the August 31 deadline for the American withdrawal from Afghanistan will not be extended despite the urging of his major NATO allies who wanted more time to evacuate their troops and citizens working in the war-ravaged country. This Biden decision was resolute, notwithstanding the fact that the proposed evacuation of thousands of US-NATO personnel, foreign nationals and Afghan citizens is unlikely to be completed by August 31.

The images that have been beamed from Kabul with thousands of desperate Afghan nationals trying to enter the airport with or without travel documents is testimony to an unfolding human tragedy whose scale is yet to be fathomed for this is only the first phase. The August 31 exit from Kabul will be recalled as a temporal punctuation of profound significance and tainted connotation for the US-led alliance that embarked on the global war on terror (GWOT) in October 2001.

Two decades later, the same Taliban who were ousted from Kabul and 'bombed into the Stone Age' have wrested power in the most unexpected manner and are now engaged in political negotiations with the global community. They have the tacit backing of two of the five permanent members of the UN Security Council and this was reflected in the mild and watered-down statements adopted by the UN Human Rights Council on August 24.

The hasty US withdrawal is confounding and projects the image of an inept and bruised America that fumbled and stumbled its way out of Afghanistan after 20 years, in the most unseemly and unplanned manner after expending considerable treasure and human lives.

The irony is that after ousting Taliban 1.0 in 2002, US-led external aid, including that by India, enabled Afghanistan to improve many of its human security indicators — particularly for women and girls and an improvement in per capita GDP and infant mortality. However, the attempt at nurturing a credible and participatory democratic ethos floundered on the deeply embedded tribal rivalries and ethnic discord, distinctive to Afghanistan, and the final collapse was symbolised by the manner in which the Afghan President Ashraf Ghani fled his country and the security forces melted away even as the Taliban moved into Kabul with not a shot being fired.

Thus the abiding perception of the hasty US exit is that it has left the country with little or no substantive gains. Thousands of Afghan citizens were also killed and injured in the long drawn out GWOT which also witnessed numerous acts of state-sponsored terrorism involving different Taliban factions that ruthlessly targeted minorities across the country and also attacked the Indian embassy in Kabul. For many Afghan citizens, the Taliban remains a dreaded entity and their desperation to flee their country has been sadly captured in a recent image of young Afghans falling to their death from the under-carriage of a US military aircraft as it was taking off from Kabul in the most chaotic and dangerous circumstances. The

A GLIMPSE ON ELECTION OF DELHI SIKH GURDWARA MANAGEMENT COMMITTEE

NEW DELHI,27th August2021--After repeated postponements due to Covid-19 epidemic, general elections for four years term Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) were at last held on 22nd August and results declared on 25th August accordingly.

These elections were conducted in a smooth and transparent manner and no untoward incident was reported due to vigilant eye of the Delhi Government. Election results were somehow astonishing because number of winners of Shiromani Akali Dal Badal faction have drastically decreased from the existing 37 in 2017 to 27 now, whereas the number of winners of Shiromani Akali Dal Delhi Sarna faction and its allies sharply increased from existing 7 in 2017 to 19 now.

The vote percentage in present elections were 37 percent as compared to 45 percent in the year 2017, out of which Badal group secured 40 percent as compared to 46 percent in the year 2017 and Sarna group and its allies secured of invalid votes were reported due to wrong marking by the voters.

Defeat of some main Sikh leaders is talk of the town in which the defeat of the present President of the DSGMC and spokesperson of Shiromani Akali Dal Badal Mr. Manjinder Singh Sirsa is one of them, who lagged behind in Punjabi Bagh ward by about 500 votes from the General Secretary of Shiromani Akali Dal Delhi Mr. Harvinder Singh Sarna.

Although Mr. Sirsa is reported to have been declared as a nominated/Co-opted candidate of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC), Sri Amritsar, which will be for the first time in the history that a defeated candidate in DSGMC elections has ever been declared as a nominee of the SGPC.

In accordance with the Delhi Sikh Gurdwaras Act 1971, the Co-option process is required to be completed within 15 days of the declaration of results of general elections i.e. upto 9th September 2021, which also includes the pro- of two members from Sikh Community of Delhi.

A meeting of the newly elected 46 DSGMC members will be called by the Director Gurdwara Elections to Co-Opt 9 members out of which firstly one nominee of SGPC and four Jathedars of Takhats i.e. Sri Akal Takhat Sahib Sri Amritsar, Takhat Sri Kesgarh Sahib Sri Anandpur Sahib, Takhat Sri Harmandir Sahib Patna Bihar and Takhat Sri Hazur Sahib Nanded Maharashtra will be Co-opted, whereas these four Jathedars have no voting right.It is pertinent to mention that Takhat Sri Damdama Sahib Talwandi Sabo Punjab has so far not been included as is already included in the 'Sikh Gurdwara Act 1925' applicable for the election of members of SGPC, Sri Amritsar.

Thereafter, two members will be Co-opted by draw of lots out of the Presidents of the Registered Singh Sabha Gurdwaras of Delhi. Lastly two Sikh representatives of Delhi will be Co-opted by voting by the 46 newly elected members present in the meeting in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote on the pattern of election of Rajya Sabha members, which is quite different from the general elections.

Delhi Sikh Gurdwara Act and rules mandates the Director Gurdwara Elections to call first meeting of all the 55 members, in which after administering Oath to all the members in the presence of Sri Guru Granth Sahib ji, a pro-tempore Chairman will be elected to conduct election of President of DSGMC. Thereafter, the newly elected President will conduct election of other office-bearers eral Secretary and Joint Secretary along with 10 members of the Executive Board.

If there are more than one candidate for any post, election will be held through secret ballot papers. Although 26 votes will be required for a winning candidate, but this number can decreased in the event of absence of some members.

During counting of votes, if more than one candidate secure equal number of maximum votes, then the winner will be decided by draw of lot. In this way, the new Executive Board will start functioning probably in the end of September 2021 after taking charge from the existing Committee, whereas the term of the new Executive Board will be two years.

In case of any dispute during the Co-option process or during the election of the Executive Board, an Election Petition can be filed by the affected party in the District Court within 15 days after depositing a sum of Rs.500 as security amount in the

Strong Warning Labels on Unhealthy Food Products as is a Human Right: Public Health Experts Call for Urgent Action

New Delhi: 27 August 2021. Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) http://www.napiindia.in/ and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.The webinar was chaired by Dr.Suneela Garg, President , Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and she said "Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth.Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs."

Experts from Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PANI) -IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest. They emphasized that marketing of packaged food items are a health hazard for children under 5 years and adolescents as they are the most vulnerable group to NCDs because of unhealthy food products consumption.Presenting evidence from around the world, Neha Khandpur, an expert and faculty of public health from University of Sao Paulo, Brazil's Centre for Nutrition said, "Warning labels have consistently been shown to be most effective at improving consumer understanding, at influencing their purchase decisions and at supporting healthy food choices.

They also are most likely to encourage product reformulation. Warning labels are the strongest nutrient-based label that India should consider implementing".According to Euromonitor estimates, the sale of UPF has increased from 2 kg per capita in 2005, to 6kg in 2019 and is expected to grow to 8kg in 2024. Similarly, beverages have gone up from less than 2 L in 2005 to about 8 L in 2019 and are expected to grow to 10 L in 2024.Dr Arun Gupta , convenor of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), a national think tank working on nutrition policy, said "This is happening at a time in India showing a tremendous rise in sales of ultra processed food (UPF) products both in the category of food and beverages. If we don't put a break to this rise now, India will join the club of obesity epidemic's developed nations like UK and USA in the coming decade.

Food industry is meant for making profits for their shareholders and will not comply unless our food and beverage regulators make it mandatory."Ms. Pushpa Girimaji, Consumer Rights Columnist and Consumer Safety Advocate pointed out that "the Consumer Protection Act of 2019 gave consumers the right to be protected from unsafe and unhealthy food through clear and unambiguous label information and appropriate warning in a manner that is easily comprehended by all, including those who cannot read or understand the label. But far more important, the Supreme Court, in Centre for Public Interest Litigation Vs Union of India, had interpreted the right to safe food as part of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution, read with Article 47, (Directive Principles of State Policy) that casts a duty on the state to raise the level of nutrition and improve public health."

So, in order to enforce these rights fully and protect citizen/consumer interest, the State or more specifically, the FSSAI, should introduce a front of label colour coding or such other easily comprehensible warning labels on foods high in sodium, sugar and saturated fat, she said. S advocated consumer education about the consequences of consuming foods high in sugar, salt and saturated fat and a ban on celebrity endorsement of such food.

When Union Finance Minister Nirmala PSB (public sector banks) recapitalisation bonds. Subsequer, which raised the budget and the fiscal deficit.Then the Reserve Bank of India to go on functioning. The banks had ties. So, the whole truth of the matter is that the government

COVERAGE REPORT

Media Kit

शाह टाइम्स
... क्योंकि जिंदा रहेगा सच

खाने-पीने की हानिकारक चीजों पर शुरू हों चेतावनी लेबल: स्वास्थ्य विशेषज्ञ

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर (फ्रंट-ऑफ-पैक) चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित शीर्ष डॉक्टरों ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है।

हाल के शोध का हवाला देते हुए कि विशेषज्ञों ने कहा है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या यूपीएफ) और पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा रहता है, जो कैंसर, हृदय रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और विभिन्न अन्य घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है। ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई), न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) सहित कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने भारत सरकार से ज्यादा चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल की अनिवार्यता पर तत्काल विचार करने की अपील की है।

शुक्रवार को आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर बल दिया। वेबिनार की अध्यक्षता डॉ. सुनीला गर्ग, अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) ने की। उन्होंने कहा, ष्स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और गैर संचारित बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे नियामकीय उपायों को अपनाएं।

Media Kit

है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बजट राशि को बढ़ाया जा सकता है।

करने वालों की संख्या बढ़ी है।

खाने-पीने की हानिकारक चीजों पर शुरू हों सख्त चेतावनी लेबल: विशेषज्ञ

नई दिल्ली, (वीअ) । यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर (फ्रंट-ऑफ-पैक) चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है।

ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई), न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) सहित कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने भारत सरकार से ज्यादा चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल की अनिवार्यता पर तत्काल विचार करने की अपील की है। शुक्रवार को आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर बल दिया। वेबिनार की अध्यक्षता डॉ. सुनीला गर्ग, अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) ने की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और गैर संचारित बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे नियामकीय उपायों को अपनाएं।

साओ पाउलो विश्वविद्यालय, ब्राजील के सेंटर फॉर न्यूट्रिशन की पब्लिक हेल्थ फैकल्टी और विशेषज्ञ नेहा खंडपुर ने दुनिया भर में जुटाए जा रहे साक्ष्यों को पेश करते हुए कहा, उपभोक्ता की समझ में सुधार करने, उनके खरीदने के निर्णयों को प्रभावित करने में ऐसे खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल का होना सबसे प्रभावी पाया गया है। इनकी वजह से उपभोक्ताओं को स्वस्थकर खाद्य उत्पाद चुनने में आसानी होती है।

Media Kit

INDIAN HORIZON

English Daily

Meetha Bhaat, Plain Rice and Pumpkin, Chana Madra, of special mountains, which order.

Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed food

New Delhi: 27 August 2021- -- Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) http://www.napiindia.in/ and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Dr.Suneela Garg, President , Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and she said "Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth ."

Experts from Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) -IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest.

Presenting evidence from around the world, Neha Khandpur, an expert and faculty of public health from University of Sao Paulo, Brazil's Centre for Nutrition said, "Warning labels have consistently been shown to be most effective at improving consumer understanding, at influencing their purchase decisions and at supporting healthy food choices.

Dr Arun Gupta , convenor of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), a national think tank working on nutrition policy, said "This is happening at a time in India showing a tremendous rise in sales of ultra processed food (UPF) products both in the category of food and beverages.

Ms. Pushpa Girimaji, Consumer Rights Columnist and Consumer Safety Advocate pointed out that "the Consumer Protection Act of 2019 gave consumers the right to be protected from unsafe and unhealthy food through clear and unambiguous label information and appropriate warning in a manner that is easily comprehended by all, including those who cannot read or understand the label. But far more important, the Supreme Court, in Centre for Public Interest Litigation Vs Union of India, had

COVERAGE REPORT

Media Kit

नई दिल्ली ▌ वर्ष- 12 ▌ अंक- 104 ▌28 अगस्त 2021 ▌ शनिवार ▌ मूल्य 3 रुपए ▌

nayaindia.com की बनाएं आदत

Andriod Phone के Playstore में NAYA INDIA मौजूद है। डाउनलोड करके ई-पेपर, सभी कॉलम, लेख अपने फोन पर पाएं। कोरोना संकट पर बेबाक, तथ्यात्मक और पठनीय जानकारी www.nayaindia.com और एप NAYA INDIA पर जितनी-जैसी है वैसी किसी और समाचार वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। अनुरोध है परिवारजनों, मित्रों से भी NAYA INDIA डाउनलोड कराए ताकि सभी जाने कि आज के वक्त में भी तेवर, बेबाकी, वैचारिकता में अपनी भाषा, हिंदी पत्रकारिता बेजोड़ है। - हरिशंकर व्यास और नया इंडिया टीम

गपशप... अंतिम पृष्ठ पर

नया इंडिया

बेबाक, बेधड़क, बेमिसाल

शनिवार फुरसत

खाने-पीने की हानिकारक चीजों पर तुरंत शुरू हों सख्त चेतावनी लेबल की व्यवस्था: स्वास्थ्य विशेषज्ञ

नई दिल्ली ■ संवाद सूत्र

यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर (फ्रंट-ऑफ-पैक) चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित शीर्ष डॉक्टरों ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है। हाल के शोध का हवाला देते हुए कि विशेषज्ञों ने कहा है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या यूपीएफ) और पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा रहता है, जो कैंसर, हृदय रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और विभिन्न अन्य घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है।

ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई), न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) http://www.napiindia.in/सहित कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने भारत सरकार से ज्यादा चीनी, नमक और वसा (saturated fat) वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल की अनिवार्यता पर तत्काल विचार करने की अपील की है। शुक्रवार को आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर बल दिया।वेबिनार की अध्यक्षता डॉ. सुनीला गर्ग, अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) ने की। उन्होंने कहा, ₹स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और गैर संचारित बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पेकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसेनियामकीय उपायों को अपनाएं।

पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी (PAN -IAP Nutrition Chapter)और एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (EFI) के विशेषज्ञों ने कहा कि फूड इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए चेतावनी लेबल संबंधी दिशा-निर्देशों में देरी करवाना चाहती है। साथ ही इसकी कोशिश है कि नियम सख्त नहीं हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिब्बा-बंद खाद्य पदार्थ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं।

COVERAGE REPORT

Media Kit

Morning India
www.sanmarglive.com
02 Tuesday
31 August 2021

Public health experts call for urgent action against unhealthy food products

OUR CORRESPONDENT

PATNA/NEW DELHI: Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non-communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra-processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity - key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non-alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) http://www.napiindia.in/ and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Dr. Suneela Garg, President, Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and she said "Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth .Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs."

Experts from Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) -IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest. They emphasized that marketing of packaged food items are a health hazard for children under 5 years and adolescents as they are the most vulnerable group to NCDs because of unhealthy food products consumption.

Presenting evidence from around the world, Neha Khandpur, an expert and faculty of public health from University of Sao Paulo, Brazil's Centre for Nutrition said, "Warning labels have consistently been shown to be most effective at improving consumer understanding, at influencing their purchase decisions and at supporting healthy food choices. They also are most likely to encourage product reformulation. Warning labels are the strongest nutrient-based label that India should consider implementing".

According to Euromonitor estimates, the sale of UPF has increased from 2 kg per capita in 2005, to 6kg in 2019 and is expected to grow to 8kg in 2024. Similarly, beverages have gone up from less than 2 L in 2005 to about 8 L in 2019 and are expected to grow to 10 L in 2024.

Dr Arun Gupta, convenor of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), a national think tank working on nutrition policy, said "This is happening at a time in India showing a tremendous rise in sales of ultra-processed food (UPF) products both in the category of food and beverages. If we don't put a break to this rise now, India will join the club of obesity epidemic's developed nations like UK and USA in the coming decade. Food industry is meant for making profits for their shareholders and will not comply unless our food and beverage regulators make it mandatory."

Ms. Pushpa Girimaji, Consumer Rights Columnist and Consumer Safety Advocate pointed out that "the Consumer Protection Act of 2019 gave consumers the right to be protected from unsafe and unhealthy food through clear and unambiguous label information and appropriate warning in a manner that is easily comprehended by all, including those who cannot read or understand the label. But far more important, the Supreme Court, in Centre for Public Interest Litigation Vs Union of India, had interpreted the right to safe food as part of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution, read with Article 47, (Directive Principles of State Policy) that casts a duty on the state to raise the level of nutrition and improve public health."

So, in order to enforce these rights fully and protect citizen/consumer interest, the State or more specifically, the FSSAI, should introduce a front of label colour coding or such other easily comprehensible warning labels on foods high in sodium, sugar and saturated fat, she said. S advocated consumer education about the consequences of consuming foods high in sugar, salt and saturated fat and a ban on celebrity endorsement of such food.

Prof. HPS Sachdev, country's leading researcher on nutrition summed up to a have strong and mandatory warning label based on the WHO thresholds of nutrient profile modelling because 50% of the children's population is suffering from cardiometabolic risk factors as per the CNNS, 2016-18 survey due to unhealthy packaged food consumption.

COVERAGE REPORT

Media Kit

RNI No. DELBIL/2015/66163

मयूर सँवाद

आपका मौहल्ला आपकी आवाज

दैनिक

वर्ष: 6 | अंक: 226 | नई दिल्ली, सोमवार, 30 अगस्त, 2021 | मूल्य: 3 रुपए | पेज : 08

नई दिल्ली, सोमवार, 30 अगस्त 2021 मयूर संवाद

खाने-पीने की हानिकारक चीजों पर तुरंत शुरू हों सख्त चेतावनी लेबल की व्यवस्था- स्वास्थ्य विशेषज्ञ

संवाददाता (दिल्ली) यदि भारत को गैर संचारित बीमारियों के संकट से लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तरह के खाद्य उत्पादों पर पैकेट के ऊपर की ओर (फ्रंट-ऑफ-पैक) चेतावनी लेबल की व्यवस्था तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित शीर्ष डॉक्टरों ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है। हाल के शोध का हवाला देते हुए कि विशेषज्ञों ने कहा है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या यूपीएफ) और पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा रहता है, जो कैंसर, हृदय रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और विभिन्न अन्य घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है। ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई), न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) http://www.napiindia.in/ सहित कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने भारत सरकार से ज्यादा चीनी, नमक और वसा (saturated fat) वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल की अनिवार्यता पर तत्काल विचार करने की अपील की है। शुक्रवार को आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत पर बल दिया। वेबिनार की अध्यक्षता डॉ. सुनीला गर्ग, अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) ने की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकारें मोटापे और गैर संचारित बीमारियों (एनसीडी) के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ज्यादा चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी वाले लेबलिंग जैसे नियामकीय उपायों को अपनाएं। पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी (PAN -IAP Nutrition Chapter) और एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (EFI) के विशेषज्ञों ने कहा कि फूड इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए चेतावनी लेबल संबंधी दिशा-निर्देशों में देरी करवाना चाहती है। साथ ही इसकी कोशिश है कि नियम सख्त नहीं हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिब्बा-बंद खाद्य पदार्थ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। हानिकारक खाद्य उत्पादों की वजह से उनमें गैर संचारी रोगों के होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। साओ पाउलो विश्वविद्यालय, ब्राजील के सेंटर फॉर न्यूट्रिशन की पब्लिक हेल्थ फैकल्टी और विशेषज्ञ नेहा खंडपुर ने दुनिया भर में जुटाए जा रहे साक्ष्यों को पेश करते हुए कहा, उपभोक्ता की समझ में सुधार करने, उनके खरीदने के निर्णयों को प्रभावित करने में ऐसे खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल का होना सबसे प्रभावी पाया गया है। इनकी वजह से उपभोक्ताओं को स्वस्थकर खाद्य उत्पाद चुनने में आसानी होती है। साथ ही, इनसे उत्पादों में सुधार की संभावना भी ज्यादा रहती है। पोषक तत्व आधारित लेबल के रूप में चेतावनी लेबल सबसे मजबूत लेबल हैं, जिन्हें भारत में लागू करने पर तत्काल विचार करना चाहिए। यूरोमॉनिटर के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2005 में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) की प्रति व्यक्ति बिक्री 2 किलोग्राम थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 6 किलोग्राम हो गई है। वर्ष 2024 तक इसके प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम तक बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह, पेय पदार्थों की बिक्री वर्ष 2005 में प्रति व्यक्ति 2 लीटर से कम थी जो वर्ष 2019 में लगभग 8 लीटर हो गया। वर्ष 2024 में इसके 10 लीटर तक हो जाने की उम्मीद है। न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता ने कहा, खाद्य और पेय, दोनों श्रेणी में भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड (यूपीएफ) प्रॉडक्ट्स की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अगर हम अभी इस पर रोक नहीं लगाते हैं, तो आने वाले दशक में भारत भी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मोटापे से ग्रसित देशों में शामिल हो जाएगा। जब तक हमारे खाद्य और पेय पदार्थ नियामक इसे अनिवार्य नहीं बनाएंगे, तब तक खाद्य उद्योग इसका पालन नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्वार्थ सिर्फ मुनाफा कमाने को लेकर है। एनएपीआई पोषण नीति पर काम कर रहा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय थिंक टैंक है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर लड़ने वाली वकील और स्तंभकार सुश्री पुष्पा गिरिमाजी ने कहा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ताओं को असुरक्षित और अस्वस्थकर खाद्य पदार्थों से उचित चेतावनी लेबल के जरिये स्पष्ट तौर पर सुरक्षित रहने का अधिकार दिया है। ऐसे लेबल जिसे सभी आसानी से समझ सकें, वो भी जो पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर सुरक्षित भोजन के अधिकार की व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में सुरक्षित भोजन की गारंटी की व्याख्या की थी, जिसे अनुच्छेद 47 के साथ पढ़ा गया था। इसमें कहा गया था कि पोषण के स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्यों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, इन अधिकारों को पूरी तरह से लागू करने और नागरिकों/उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य, खासकर खस्ड्ड को ज्यादा सोडियम, चीनी और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों पर लेबल कलर कोडिंग या ऐसे अन्य आसानी से समझे जाने वाले चेतावनी लेबल को पेश करना चाहिए।

COVERAGE REPORT

JANJIVAN
World of News

बीमारियों के खतरे से बचाने के लिए फूड पैकेट चेतावनी तुरंत शुरू करना जरूरी

बाल रोग, पोषण और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आगे आए

– Aug 28, 2021 in All Categories, HomeSlider
0

अमलेंदु भूषण खां / नई दिल्ली / देश के शीर्ष डॉक्टरों और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खाने-पीने की चीजों के पैकेट पर ऊपर की ओर सेहत संबंधी चेतावनी (पैक वार्निंग) तत्काल शुरू करने को लोक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद जरूरी बताया है। इन्होंने देश में संक्रामक रोग कोरोना के साथ गैर संक्रामक रोगों के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए इसे जरूरी पाया है।

इन्होंने वैज्ञानिक शोधों का हवाला दिया है जिनमें बताया गया है कि ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से होने वाला मोटापा कैंसर, हृदय रोगों और लीवर संबंधी रोगों का बड़ा कारण बन रहा है।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आइएपीएसएम) की अध्यक्ष डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा "स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकारें ज्यादा चीनी, नमक या वसा वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के पैकेट पर ऊपर की ओर ही चेतावनी वाले लेबल के नियम अपनाएं।" यह बात उन्होंने बीपीएनआइ की ओर से इस विषय पर आयोजित वेबिनार में शुक्रवार को कही।

READ ALSO

सुप्रीम कोर्ट का सुपरटेक नोएडा के ट्विन टावर गिराने का आदेश, फ्लैट खरीदने वालों को दो माह में मिलेगा रिफंड

अफगानिस्तान जाने की चाहत ने अफगानी युवक को पहुंचाया पुलिस की गिरफ्त में

पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी और एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने भी इस पर जोर दिया। साथ ही कहा कि फूड इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए ऐसी चेतावनी की व्यवस्था में देरी करवाना चाहती है। साथ ही इसकी कोशिश है कि नियम सख्त नहीं हों।

https://www.janjivan.com/?p=40882

Nectarine Next generation coverage reports Free Trial

बाल रोग, पोषण और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले देश को बीमारियों के खतरे से बचाने के लिए फूड पैकेट चेतावनी तुरंत शुरू करना जरूरी

Special Correspondent द्वारा - 28/08/2021

Nectarine Free Trial Next generation coverage reports

लोकप्रिय

हिमाचल | जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी, लाहौल-स्पीति...
31/08/2021

हिमाचल | राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया एशिया के सबसे...
28/08/2021

हिमाचल | मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन बारिश का अनुमान,...
27/08/2021

हिमाचल | सेब खरीद पर गहराते संकट

सेहत संबंधी चेतावनी (पैक वार्निंग) तत्काल शुरू करने को लोक स्वास्थ्य (Public Health) के लिहाज से बेहद जरूरी बताया है. इन्होंने देश में संक्रामक रोग कोरोना के साथ गैर संक्रामक रोगों के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए इसे समय कि जरूरत बताया है.

विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक शोधों का हवाला दिया है जिनमें बताया गया है कि ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से होने वाला मोटापा कैंसर, हृदय रोगों और लीवर संबंधी रोगों का बड़ा कारण बन रहा है.

सेहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आइएपीएसएम) की अध्यक्षा डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा "स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है. इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकारें ज्यादा चीनी (Sugar), नमक (Salt) या वसा (Fat) वाले हानिकारक खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के पैकेट पर ऊपर की ओर ही चेतावनी वाले लेबल के नियम अपनाएं." यह बात उन्होंने बीपीएनआइ की ओर से इस विषय पर आयोजित वेबिनार में शुक्रवार 27 अगस्त को कही.

टालने में जुटी है इंडस्ट्री

पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी और एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने भी इस पर जोर दिया. साथ ही कहा कि फूड इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए ऐसी चेतावनी की व्यवस्था में देरी करवाना चाहती है. साथ ही फूड इंडस्ट्री इस कोशिश में भी लगे हुए है कि नियम सख्त ना हों.

शोधों में चेतावनी पाई गई कारगर

ब्राजील के साओ पाउलो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर न्यूट्रिशन में पब्लिक हेल्थ की अध्यापिका और विशेषज्ञ नेहा खंडपुर ने दुनिया भर में जुटाए जा रहे साक्ष्यों को पेश करते हुए कहा कि उपभोक्ता को जागरुक करने और उनके निर्णय को प्रभावित करने में ऐसी चेतावनी सबसे प्रभावी पाई गई है. इसकी मदद से लोग बेहतर उत्पाद चुन पाते हैं.

भारत में तेजी से बढ़ रहा है मोटापे का खतरा

https://www.panchayattimes.com/to-save-indians-from-diseases-food-labeling-must-says-specialists/

English | தமிழ் | বাংলা | മലയാളം | हिंदी | मराठी | Business | बिज़नेस | Insurance

जनसत्ता

होम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल विचार राज्य मनोरंजन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी करियर फोटो ऑटो वीडियो ई-पेपर गेम्स

बच्चों और किशोरों के लिए गंभीर खतरा हैं डिब्बा-बंद खाद्य पदार्थ, तुरंत शुरू हो सख्त चेतावनी लेबल की व्यवस्था

उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए काम करने वालीं वकील सुश्री पुष्पा गिरिमाजी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में सुरक्षित भोजन की गारंटी की व्याख्या की थी, जिसे अनुच्छेद 47 के साथ पढ़ा गया था। इसमें कहा गया था कि पोषण के स्तर को...

ज Jansatta / Aug 28

https://www.jansatta.com/lifestyle/canned-foods-serious-threat-to-children-and-adolescents-system-of-strict-warning-labels-should-be-started-immediately/1799630/

वीडियो राज्य चुनें Download App

खाने पीने वाली पैकेटबंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी हो चेतावनी, इन संगठनों ने की मांग

है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में सुरक्षित भोजन की गारंटी की व्याख्या की थी, जिसे अनुच्छेद 47 के साथ पढ़ा गया था

कुमार कुन्दन
Publish Date - 8:13 pm, Sat, 28 August 21
Edited By: शुभांगी गोयल

Unhealthy Food Packet पर हेल्थ वार्निंग की चेतावनी

देश भर के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे नुकसानदेह पैकेटबंद खाने-पीने की चीजों को ले कर चेतावनी दी है. इन्होंने कहा है कि अगर वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले उत्पादों पर पैकेट को लेकर तुरंत हेल्थ वार्निंग शुरू नहीं की गई तो देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा. कारोबार से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैकेटबंद खाने का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है.

पोषण और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले ये संगठन पैकेटबंद चीजों पर सामने की ओर चेतावनी के नियम को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आए हैं- न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई), इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम), पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी, एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई).

https://www.tv9hindi.com/india/warning-issued-through-labels-on-packaged-food-items-these-organizations-demanded-799628.html?

AhmedabadMirror

1 / 1 Warning labels on junk food must to curb childhood obesity in India

Top Doctors, Including Paediatricians, And Public Health Experts Gathered To Discuss The Urgent Need For The Adoption Of Front-Of-Pack Warning Labels On All Unhealthy Food Products If India Is To Safeguard Peoples Lives From The Looming Crisis Of Non Communicable Diseases.

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity -- key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) and several public health organisations called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Suneela Garg, President, Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM).

millenniumpost
NO HALF TRUTHS

Experts demand rollout of strict front packaging norms at the earliest

Team MP 28 Aug 2021 12:02 AM

New Delhi: In view of the increasing threat of non-communicable diseases among children due to intake on high amount of salt, fat and sugar o asked the Food Safety Standard Authority of India (FSSAI) to implement package levelling norms at earliest.

Citing scientific researches, the experts have stated that excessive intake of salt, fat and sugar contents in packaged food products is becomin

Consumer rights activist and columnist Pushpa Girimaji said, "To protect the interest of citizens, food items with high salt, sugar and fat should understandable warning labels."

Also Read - Schools and colleges in TN resume physical classes with Covid-19 SOPs

While addressing a webinar, Dr Sunila Garg, who heads Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM), said, "Everyone has the ri the wealth of the nation. So, it is a must for state and central governments to put warning labels on top of the front of packaging of food produc

Experts from the Pediatric and Adolescent Nutrition Society and Epidemiology Foundation of India have said that the food industry wants to del industry is trying to ensure that the rules are not strict.

Also Read - Ladakh reports 5 new COVID-19 cases

Citing research findings, Neha Khandpour, professor of public health at the Centre for Nutrition at the University of So Paulo, Brazil, stressed tha informing consumers and influencing their decisions as people are able to select better products on the basis of such warnings.

"There has been a rapid increase in the use of food products that cause sickness. In the coming decades, India will also join the obesity-prone c mandatory, else industry wouldn't follow it," said Arun Gupta, who is convener of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPI), at a webinar orgar

Like 11K Share
Follow @mpostdigital 1,035 followers

http://www.millenniumpost.in/nation/experts-demand-rollout-of-strict-front-packaging-norms-at-the-earliest-451126

the pioneer

FEATURES Vivacity Health Travel Show Time BackPack Special Avenues AGENDA - THE S

Experts for adopting front-of-pack labels on all processed foods

Monday, 30 August 2021 | PNS | New Delhi

SHARE

Ultra-processed food (UPF) is increasingly under fire with health experts warning that if India is to safeguard its people's lives particularly children from the looming crisis of deadly non communicable diseases (NCDs), it should urgently and mandatorily adopt front-of-pack warning labels (FOPL) on all high-salt, sugar and fat containing edible items.

They have reasons. According to Euro monitor estimates, the sale of UPF has increased from 2 kg per capita in 2005 to 6kg in 2019 and is expected to grow to 8kg in 2024. Similarly, beverages have gone up from less than 2 Litres in 2005 to about 8 Litres in 2019 and are expected to grow to 10 Litres in 2024. Unchecked consumption of these UPF is leading the country's youth to overweight and obesity.

"Right-to-health is a fundamental right of every person. Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of wasteful nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs," said Dr.Suneela Garg, President , Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM), at a webinar held here to push for FOPL as human right.

The discussion comes amid the background of the country's top food regulator's, FSSAI, dilly dallying in implementation of the FOPLs which are still being discussed with the stakeholders.

Neha Khandpur, faculty of public health from University of Sao Paulo, Brazil's Centre for Nutrition talked about global practices, asserting that "Warning labels have consistently been shown to be most effective at improving consumer understanding, at influencing their purchase decisions and at supporting healthy food choices. They also are most likely to encourage product reformulation. Warning labels are the strongest nutrient-based label that India should consider implementing".

Dr Arun Gupta , convenor of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), a national think tank working on nutrition policy, warned that "India is showing a tremendous rise in sales of UPF items both in the category of food and beverages.

"If we don't put a break to this rise now, India will join the club of obesity epidemic's developed nations like UK and USA in the coming decade. Food industry is meant for making profits for their shareholders and will not comply unless our food and beverage regulators make it mandatory," he said. Echoing similar views, Pushpa Girimaji, consumer rights columnist and consumer safety advocate pointed out that "the Consumer Protection Act of 2019 gave consumers the right to be protected from unsafe and unhealthy food through clear and unambiguous label information and appropriate warning in a manner that is easily comprehended by all, including those who cannot read or understand the label."

She also talked about PILs filed in the Supreme Court in this regard that ensures the right to safe food as part of the right to life. According to the global data, nearly 5.8 million people or 1 in 4 Indians are at a risk of dying from an NCD before they reach the age of 70.

Ultra-processed foods are ready-to-eat or ready-to-heat items often high in added sugar, sodium, and carbohydrates, and low in fiber, protein, vitamins, and minerals. They typically contain added sugars, hydrogenated oils, and flavor enhancers

https://www.dailypioneer.com/2021/india/experts-for-adopting--front-of-pack-labels-on-all-processed-foods.html

HEALTHWIRE
WELLNESS AT A CLICK

HOME हिंदी EXCLUSIVES EXPERTS OPINION LATEST NEWS COVID

Home › Experts Opinion › Strong Warning Labels On Unhealthy Food Products As Is A Human Right:...

Experts Opinion | Latest News | Spotlight

Strong Warning Labels On Unhealthy Food Products As Is A Human Right: Public Health Experts Call For Urgent Action

Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products

By Healthwire Bureau - August 28, 2021 11:00

Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non-communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra-processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non-alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider the application of mandatory warning labels on

https://www.healthwire.co/strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products-as-is-a-human-right-public-health-experts-call-for-urgent-action/

sify.com

Doctors, health experts call for strong warning labels on unhealthy food products

Source :IANS
Author :IANS
Last Updated: Tue, Aug 31st, 2021, 15:20:20hrs

New Delhi, Aug 31 (IANS) Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

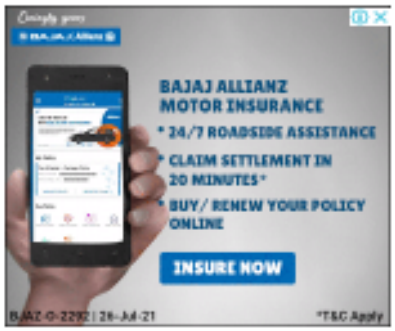

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity -- key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) and several public health organisations called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Suneela Garg, President, Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM).

"Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth. Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs," she said.

Experts from the Paediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) - IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest.

They emphasized that marketing of packaged food items are a health hazard for children under five years and adolescents as they are the most vulnerable group to NCDs because of unhealthy food products consumption.

https://www.sify.com/news/doctors-health-experts-call-for-strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products-news-national-vi5jOucdgbhdi.html

Doctors, health experts call for strong warning labels on unhealthy food products

They emphasised that marketing of packaged food items are a health hazard for children under five years and adolescents as they are the most vulnerable group to NCDs because of unhealthy food products consumption.

By Newsd
Published on :Tue 31st August 2021, 03:53 PM

Follow Newsd On Google News

Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) and several public health organisations called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Suneela Garg, President, Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM).

https://newsd.in/doctors-health-experts-call-for-strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products/

THE NEW INDIAN EXPRESS

Doctors, health experts call for strong warning labels on unhealthy food products

Experts pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest

Edex Live
Edex Live

Image for representation | Pic: Express

Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity — key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty

https://www.edexlive.com/news/2021/aug/31/doctors-health-experts-call-for-strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products-23662.html

Home » News » Lifestyle » Covid19: कोरोना काल में सेहत के लिए बड़ा खतरा बन रहे Food Packets, सावधान कर रहे हेल्थ एक्सपर्ट्स

Covid19: कोरोना काल में सेहत के लिए बड़ा खतरा बन रहे Food Packets, सावधान कर रहे हेल्थ एक्सपर्ट्स

देश को बीमारियों के बड़े खतरे से बचाना है तो Food Packets उत्पादों पर सेहत संबंधी चेतावनी शुरू करना बहुत जरूरी है. (सांकेतिक फोटो)

Food Packets: विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर देश को बीमारियों के बड़े खतरे से बचाना है तो ऐसे Food Packets उत्पादों पर सेहत संबंधी चेतावनी तुरंत शुरू करना बहुत जरूरी है. इन उत्पादों को ज्यादा स्वादिष्ट बना कर लोगों को इनकी लत लगाने के लिए इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में वसा, नमक और चीनी का उपयोग हो रहा है जिससे कैंसर, हृदय रोगों और लीवर संबंधी रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है.

NEWS18HINDI

LAST UPDATED : SEPTEMBER 01, 2021, 15:59 IST

नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) काल में पैकेटबंद खाने-पीने (Food packet) की चीजें सेहत के लिए कई तरह के खतरे पैदा कर रही हैं. वसा, नमक और चीनी की खतरनाक मात्रा के स्वास्थ्य (Health) पर पड़ने वाले असर को ले कर देश भर के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और संगठनों ने आगाह किया है. इन्होंने मांग की है कि अब जल्द से जल्द ऐसे पैकेटबंद खाने-पीने के सामानों पर भी ऊपर की ओर ही स्पष्ट चेतावनी लगाई जाए.

कई देशों में तंबाकू उत्पादों (Tobacco Products) की तरह शुरू की गई फ्रंट ऑफ पैकेट लेबल की व्यवस्था से लोगों की खान-पान संबंधी आदतों में तुरंत बदलाव देखा गया है. विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर देश को बीमारियों के बड़े खतरे से बचाना है तो ऐसे उत्पादों पर सेहत संबंधी चेतावनी तुरंत शुरू करना बहुत जरूरी है.

इन उत्पादों को ज्यादा स्वादिष्ट बना कर लोगों को इनकी लत लगाने के लिए इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में वसा, नमक और चीनी का उपयोग हो रहा है जिससे कैंसर, हृदय रोगों और लीवर संबंधी रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है.

पैकेटबंद खाने-पीने के सामानों पर चेतावनी लागू करने की मांग

सेहत के लिए खतरा पैदा कर रहे पैकेटबंद खाने-पीने के सामानों पर चेतावनी लागू करने की मांग के समर्थन में स्वास्थ्य और न्यूट्रीशन के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठन सामने आए हैं. न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (NAPI), इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (IAPSM), पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी, एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (BPNI) जैसे संगठनों ने इसे तत्काल लागू करने को जरूरी बताया है.

सेहत के लिहाज से बेहतर उत्पाद चुनने में मदद करती है चेतावनी

इस विषय पर आयोजित एक वेबिनार के दौरान पोषण विशेषज्ञ और ब्राजील (Brazil) की साओ पाउलो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर न्यूट्रिशन में अध्यापक नेहा खंडपुर ने ऐसी चेतावनी के प्रभाव को साबित करने के लिए दुनिया भर के कई शोधों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में हुए शोध के आधार पर यह स्पष्ट है कि नमक, चीनी और वसा के संबंध में लोगों को स्पष्ट जानकारी देने वाली चेतावनी बहुत प्रभावी होती है. ऐसी चेतावनी लोगों को सेहत के लिहाज से बेहतर उत्पाद चुनने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें: आधी रात को उठकर खाते हैं ये 5 चीजें तो आज ही बदल लें ये आदत

एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने सचेत किया है कि यह कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही मोटे मुनाफे को देखते हुए ये ऐसी कोई भी व्यवस्था लागू होने में अड़चन डालने की पूरी कोशिश करेंगे.

https://hindi.news18.com/news/lifestyle/recipe-food-packets-are-becoming-a-big-threat-to-health-during-corona-era-health-experts-are-cautioning-3721453.html

SOCIALNEWS.XYZ
The Millennial Media

Doctors, health experts call for strong warning labels on unhealthy food products

POSTED BY: GOPI AUGUST 31, 2021

New Delhi, Aug 31 (SocialNews.XYZ) Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity -- key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) and several public health organisations called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

https://www.socialnews.xyz/2021/08/31/doctors-health-experts-call-for-strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products/

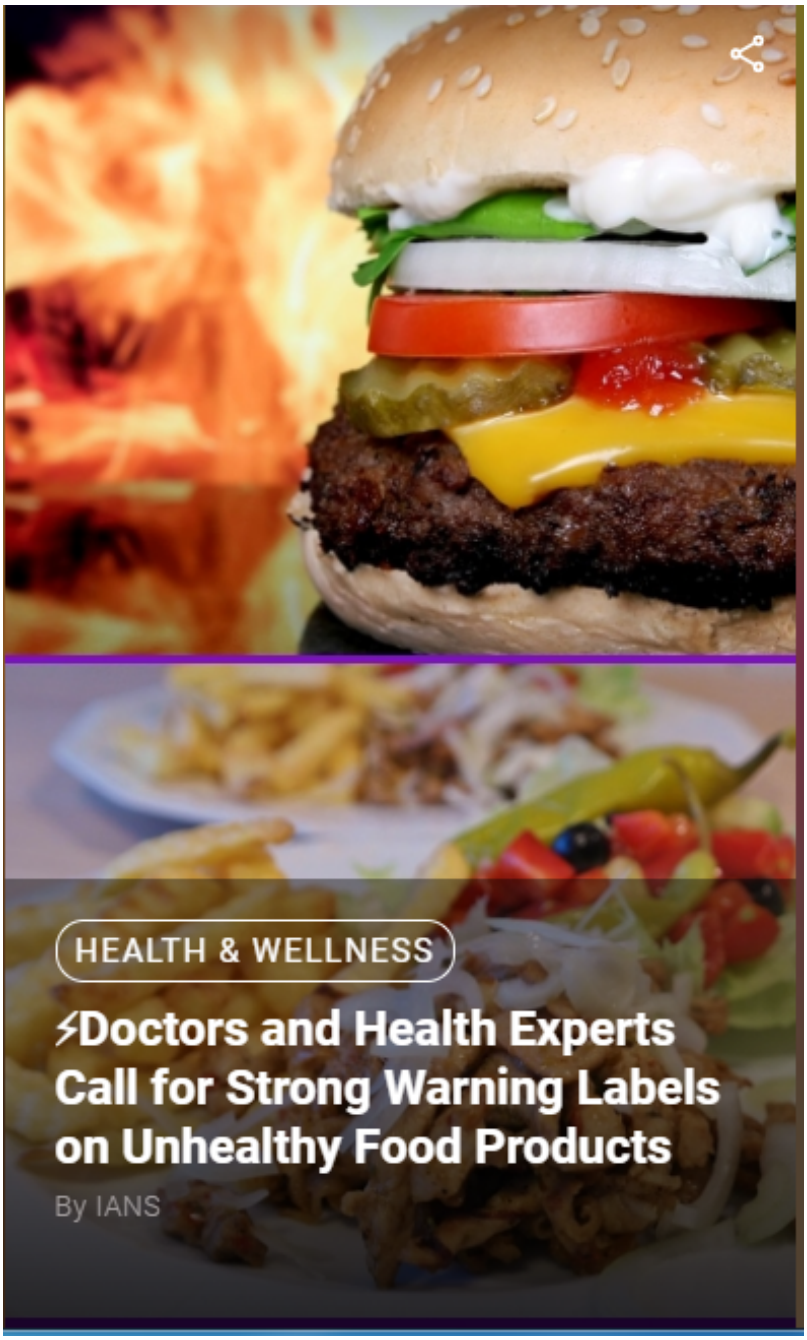

LATESTLY

1 https://www.latestly.com/quickly/lifestyle/health-wellness/doctors-and-health-experts-call-for-strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products-2800537.html

Doctors, Health Experts Call for Strong Warning Labels on Unhealthy Food Products

Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

Health & Wellness IANS | Aug 31, 2021 06:37 PM IST

A- A+

Junk food from around the world (Photo Credits: Pixabay)

New Delhi, Aug 31: Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity -- key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) and several public health organisations called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Suneela Garg, President, Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM).

"Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth. Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on fo ... ive

Google News Telegram Bot

How to Correctly... Padma Lakshmi Birthday Spe

https://www.latestly.com/lifestyle/health-wellness/doctors-health-experts-call-for-strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products-2800537.html

ET THE ECONOMIC TIMES

ET Healthworld.com
From The Economic Times

Doctors, health experts call for strong warning labels on unhealthy food products

Top doctors, including paediatricians, and public health experts called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

IANS • August 31, 2021, 18:49 IST

New Delhi: Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity -- key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) and several public health organisations called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Suneela Garg, President, Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM).

"Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth. Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs," she said.

Experts from the Paediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) - IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest.

https://health.economictimes.indiatimes.com/news/diagnostics/doctors-health-experts-call-for-strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products/85800537

India News Republic

Health

Doctors and health professionals demand strong warning labels from unhealthy foods, Health News and ET Health World

New Delhi: Leading, including pediatricians, to discuss the urgent need for India to adopt front-line warning labels on all unhealthy foods to save people's lives from the impending crisis of non-communicable diseases Doctors and public health experts gathered.

Citing recent studies that overdose of super-processed foods (UPFs) and beverages can lead to overweight and obesity. It is a major risk factor for cancer, cardiovascular disease, non-alcoholic fatty liver disease and various other fatal illnesses. BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), and some public health organizations urgently consider applying mandatory warning labels to ultra-processed foods and foods high in sugar / salt or saturated fat. I asked.

The webinar was chaired by Suneela Garg, Chairman of the Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM).

"The right to health is the fundamental right of all human beings, and the health of young people is the wealth of the country. Therefore, in the context of India, the state states such as warning labels on the front of food and beverage packages containing excessive amounts. Regulatory measures need to be adopted. Important nutrients such as sugar to address the increasing burden of obesity and NCD. "

Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PANI) Experts-IAP Nutrition Branch and Indian Epidemiology Foundation (IEF) want the food industry to delay and dilute warning label guidelines due to vested interests. I pointed out.

They emphasized that the sale of packaged foods is a health hazard for children and adolescents under the age of five, as it is the most vulnerable group to NCDs due to the consumption of unhealthy foods.

Neha Khandpur, an expert at the University of São Paulo, a nutrition center in Brazil, and the Faculty of Public Health, presented evidence from around the world, saying: Supporting healthy food selection. It is also most likely to facilitate product represcription. The warning label is the strongest nutrition-based label that India should consider

Buziness Bytes

FOLLOW US ON Google News

Experts want strong front-of-package food labels as human rights

4 days ago

TBB BUREAU

NEW DELHI, AUG 27

If India is to safeguard its people's lives particularly children from the looming crisis of deadly non-communicable diseases (NCDs), it need to urgently and mandatorily adopt front-of-package warning labels (FOPWL) on all ultra processed foods (UPF), health experts said on Friday.

According to Euromonitor estimates, the sale of UPF has increased from 2 kg per capita in 2005, to 6 kg in 2019; and is expected to go up to 8 kg by the year 2024. Similarly, beverages sale have gone up from less than 2 litres in 2005 to about 8 litres in 2019 and is estimated to touch to 10-litre mark by 2024.

At a webinar held here today, the experts discussed the issue threadbare and cited recent research noting that overconsumption of ultra processed foods and beverages is leading to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases. They called upon the Government to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat

https://thebusinessbytes.com/health/experts-want-strong-front-of-package-food-labels-as-human-rights/

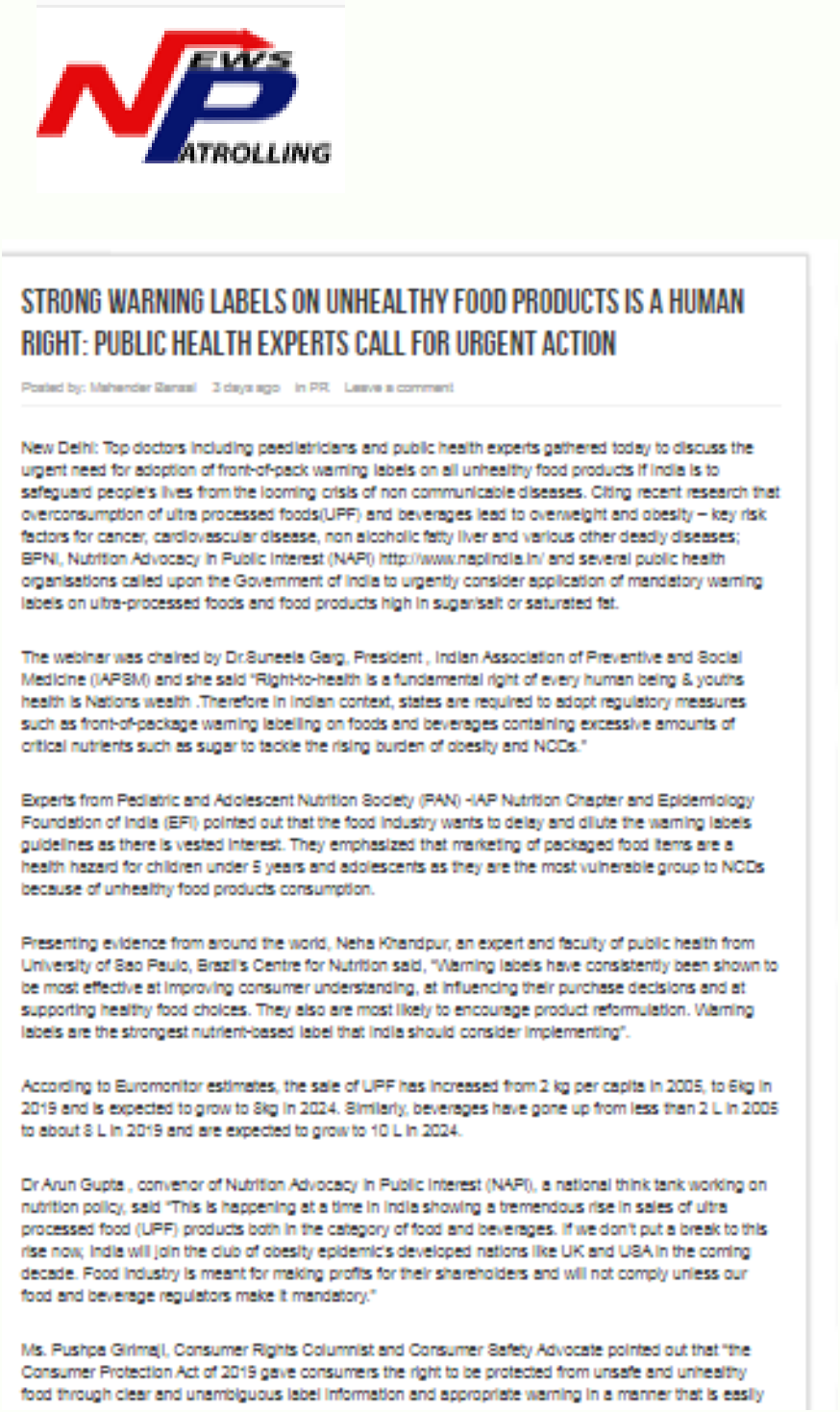

STRONG WARNING LABELS ON UNHEALTHY FOOD PRODUCTS IS A HUMAN RIGHT: PUBLIC HEALTH EXPERTS CALL FOR URGENT ACTION

Posted by: Mahender Bansal 2 days ago In PR Leave a comment

New Delhi: Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPI) http://www.napiindia.in/ and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Dr.Suneela Garg, President , Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and she said "Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth .Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs."

Experts from Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) -IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest. They emphasized that marketing of packaged food items are a health hazard for children under 5 years and adolescents as they are the most vulnerable group to NCDs because of unhealthy food products consumption.

Presenting evidence from around the world, Neha Khandpur, an expert and faculty of public health from University of Sao Paulo, Brazil's Centre for Nutrition said, "Warning labels have consistently been shown to be most effective at improving consumer understanding, at influencing their purchase decisions and at supporting healthy food choices. They also are most likely to encourage product reformulation. Warning labels are the strongest nutrient-based label that India should consider implementing".

According to Euromonitor estimates, the sale of UPF has increased from 2 kg per capita in 2005, to 6kg in 2019 and is expected to grow to 8kg in 2024. Similarly, beverages have gone up from less than 2 L in 2005 to about 8 L in 2019 and are expected to grow to 10 L in 2024.

Dr Arun Gupta , convenor of Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPI), a national think tank working on nutrition policy, said "This is happening at a time in India showing a tremendous rise in sales of ultra processed food (UPF) products both in the category of food and beverages. If we don't put a break to this rise now, India will join the club of obesity epidemic's developed nations like UK and USA in the coming decade. Food industry is meant for making profits for their shareholders and will not comply unless our food and beverage regulators make it mandatory."

Ms. Pushpa Girimaji, Consumer Rights Columnist and Consumer Safety Advocate pointed out that "the Consumer Protection Act of 2019 gave consumers the right to be protected from unsafe and unhealthy food through clear and unambiguous label information and appropriate warning in a manner that is easily

https://www.newspatrolling.com/strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products-is-a-human-right-public-health-experts-call-for-urgent-action/

COVERAGE REPORT

Strong Warning Labels On Unhealthy Food Products Is A Human Right: Public Health Experts Call For Urgent Action

August 29, 2021 9:55 am LifeStyle

New Delhi: Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) http://www.napiindia.in/ and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Dr.Suneela Garg, President , Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM) and she said "Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth .Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs."

Experts from Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) -IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest. They emphasized that marketing of packaged food items are a health hazard for children under 5 years and adolescents as they are the most vulnerable group to NCDs because of unhealthy food products consumption.

https://onlinemediarelease.com/strong-warning-labels-on-unhealthy-food-products-is-a-human-right-public-health-experts-call-for-urgent-action/

COVERAGE REPORT

Top doctors including paediatricians and public health experts gathered today to discuss the urgent need for adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard people's lives from the looming crisis of non communicable diseases. Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods(UPF) and beverages lead to overweight and obesity – key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi) http://www.napiindia.in/ and several public health organisations called upon the Government of India to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

Experts from Pediatric and Adolescent Nutrition Society (PAN) -IAP Nutrition Chapter and Epidemiology Foundation of India (EFI) pointed out that the food industry wants to delay and dilute the warning labels guidelines as there is vested interest. They emphasized that marketing of packaged food items are a health hazard for children under 5 years and adolescents as they are the most vulnerable group to NCDs because of unhealthy food products consumption.

Presenting evidence from around the world, Neha Khandpur, an expert and faculty of public health from University of Sao Paulo, Brazil's Centre for Nutrition said, *"Warning labels have consistently been shown to be most effective at improving consumer understanding, at influencing their purchase decisions and at supporting healthy food choices. They also are most likely to encourage product reformulation. Warning labels are the strongest nutrient-based label that India should consider implementing".*

https://www.gadget-innovations.com/2021/08/strong-warning-labels-on-unhealthy-food.html

COVERAGE REPORT

daijiworld.com
A portal linking the West Coast of India and the World

Doctors, health experts call for strong warning labels on unhealthy food products

Tue, Aug 31 2021 05:28:45 PM

FOR ADVICE ON CANCER TREATMENTS
ASK OUR DOCTORS
DIAGNOSIS | TREATMENT | PROCEDURES
BOOK NOW
Ads by Google
Stop seeing this ad
Why this ad?

New Delhi, Aug 31 (IANS): Top doctors, including paediatricians, and public health experts gathered to discuss the urgent need for the adoption of front-of-pack warning labels on all unhealthy food products if India is to safeguard peoples lives from the looming crisis of non communicable diseases.

Citing recent research that overconsumption of ultra processed foods (UPF) and beverages lead to overweight and obesity -- key risk factors for cancer, cardiovascular disease, non alcoholic fatty liver and various other deadly diseases; BPNI, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPI) and several public health organisations called upon the Centre to urgently consider application of mandatory warning labels on ultra-processed foods and food products high in sugar/salt or saturated fat.

The webinar was chaired by Suneela Garg, President, Indian Association of Preventive and Social Medicine (IAPSM).

"Right-to-health is a fundamental right of every human being & youths health is Nations wealth. Therefore in Indian context, states are required to adopt regulatory measures such as front-of-package warning labelling on foods and beverages containing excessive amounts of critical nutrients such as sugar to tackle the rising burden of obesity and NCDs," she said.

https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=868631

COVERAGE REPORT

Ends